RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 10 JUNE TO 16 JUNE 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 42 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

एचपीसीएल की विजग रिफाइनरी के 3 अरब डॉलर की विस्तार योजना में Page 2

सरकार 15 प्रतिशत कंपनी कर दर का लाभ लेने की समयसीमा बढ़ाने पर करेगी विचार: वित्त मंत्री Page 3

दूर्वा से भी प्रसन्न होते हैं गजानन Page 6

editoria!

इकॉनमी: रेटिंग से आगे

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 22 साल में पहली बार भारत की सॉवरेन रेटिंग गिराते हुए इसे बीएए2 से बीएए3 पर ला दिया है, जो निवेश की दृष्टि से सबसे निचली रेटिंग है। इससे पहले इस संस्था ने जून 1998 में वाजपेयी सरकार द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत की रेटिंग गिराई थी। सामान्य स्थिति इस वक्त भी नहीं है। कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की जकड़न से पूरा विश्व पस्त पड़ा है। गौर करने की बात है कि भारत कोई अकेला देश नहीं है जिसकी रेटिंग गिराई गई है। मूडीज ने सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका समेत 21 और देशों की रेटिंग भी गिराई है, जो सभी विकासशील व उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। लेकिन उनका जिक्र करके अगर हम खुद को भुलावे में रखते हैं तो हालात की गंभीरता को समझने में हमसे भारी चूक हो जाएगी। सचाई यह है कि मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग गिराने का फैसला कोरोना के दुष्प्रभावों पर आधारित नहीं है। यह फैसला भारत के नीति निर्माता संस्थानों की क्षमता और हमारे वित्तीय क्षेत्र के दबावों को लेकर मूडीज की समझ बताता है। यह दोहराना भी जरूरी है कि इसी रेटिंग एजेंसी ने तीन साल पहले 2017 में आर्थिक सुधारों की संभावना को आधार बनाकर भारत की रेटिंग ऊंची की थी। वे अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं और मूडीज को इनके पूरे होने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। सरकार के सामने कठिनाइयां पहले भी कम नहीं थीं, पर अब रेटिंग गिराए जाने के बाद आगे की राह थोड़ी और मुश्किल होने वाली है। जिन कंपनियों के चीन से निकलकर भारत आने की उम्मीद की जा रही थी, उनके निवेशकों को इस फैसले पर हामी भरने में हिचक हो सकती है। संस्थागत विदेशी निवेशकों के लिए भी भारत पर दांव लगाना पहले की अपेक्षा और कठिन हो जाएगा। जहां तक देश के अंदर निवेश बढ़ाने की बात है तो वह प्रक्रिया भी सरकार और रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद जोर नहीं पकड़ रही। ब्याज दरों में लगातार भारी-भरकम कटौती के बावजूद उद्योग जगत बैंकों से लोन लेने का रुझान नहीं दिखा रहा। जाहिर है, देश में मांग की कमी के अलावा मजदूरों के शहरों से गांवों की ओर पलायन ने भी कारखानों में पूरी क्षमता से उत्पादन को सपने जैसा बना दिया है। सरकार इन मुश्किलों से अनजान नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री ने सीआईआई की सालाना बैठक में उद्योग जगत के दिग्गजों को संबोधित करते हुए उन्हें उत्साहित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जिस तरह के गतिरोध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया है उसके टूटने में अभी वक्त लगने वाला है। सरकार को आर्थिक सुधारों की राह पर आगे बढ़ते हुए ऐसे बहुत सारे कदम उठाने होंगे जिनसे देश-विदेश के निवेशकों के अंदर नई उम्मीद जगे और वे रेटिंग एजेंसियों के आकलन को एक तरफ रखकर नए निवेश की हिम्मत जुटा सकें।

पहले सरकारों ने बढ़ाया तेल पर टैक्स अब कंपनियां ग्राहकों से वसूल रहीं घाटा

नई दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग तीन महीने तक स्थिर रहने के बाद एक बार फिर उछाल मारने लगी हैं। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले तीन महीने में जब दाम स्थिर थे तो सरकारों ने तेल पर टैक्स बढ़ाकर अपना खजाना भरा और अब कंपनियां इसकी भरपाई के लिए ग्राहकों से वसूली कर रही हैं। दरअसल, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को विनियमित कर रखा है। यानी वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी या कमी के आधार पर घरेलू बाजार में इसकी कीमत तय की जाती है। हालांकि, इस समय वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम 41.25 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं।

बावजूद इसके खुदरा बाजार में रविवार और सोमवार को जहां पेट्रोल 60-60 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं मंगलवार को 54 पैसे दाम बढ़े। इस तरह, तीन दिनों में 1.74 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल 73 रुपये लीटर तो मुंबई में 80.01 रुपये लीटर पहुंच गया है। डीजल भी इस दौरान पौने दो रुपये महंगा हो चुका है। वैश्विक बाजार में तेल कीमतों में गिरावट का लाभ सरकार ने उपभोक्ताओं को देने के बजाए उत्पाद शुल्क और वैट बढ़ाकर खुद ले लिया। सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल-डीजल पर 3 रुपये उत्पाद शुल्क बढ़ाया था और कंपनियों ने दैनिक समीक्षा रोक दी थी। इसके बाद 6 मई को फिर पेट्रोल पर 10 रुपये लीटर और डीजल पर 13 रुपये लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाया। अलग-अलग राज्यों ने इस पर वैट भी बढ़ा दिया था।

19 रुपये के पेट्रोल पर 53 रुपये टैक्स

फिलहाल रिफाइनरी से निकले प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 19 रुपये है। इस पर लगभग 35 रुपये उत्पाद शुल्क लगता है और 18 रुपये राज्य सरकार का वैट। साथ में ढुलाई भाड़ा और डीलर कमीशन मिलाकर यह उपभोक्ताओं को दिल्ली में 73 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

क्रूड 1 डॉलर सस्ता तो 29 हजार करोड़ की बचत

भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत एक डॉलर सस्ती होने पर देश को 29 हजार करोड़ की बचत होती है और उपभोक्ताओं को पेट्रोल पर प्रति लीटर 50 पैसे कम चुकाने पड़ते हैं। यानी हर 10 डॉलर सस्ता होने से देश को 2.9 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

दो साल में नौ बार बढ़ा उत्पाद शुल्क

नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच केंद्र सरकार ने 9 बार उत्पाद शुल्क बढ़ाया। यानी 2014 से 2018-19 तक केंद्र ने तेल पर टैक्स के जरिये 10 लाख करोड़ कमाए। राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाकर 2014-15 में 1.3 लाख करोड़ कमाया तो 2017-18 में 1.8 लाख करोड़ वसूला। इस बार भी जब कीमतें घटनी शुरू हुई तो केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया।

Crude Oil

सऊदी अरब ने बढ़ाए कच्चे तेल के दाम

नयी दिल्ली। एजेंसी

सऊदी अरब ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम दो दशकों में सबसे बड़ी वृद्धि की है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और रूस सहित इसके सहयोगी जुलाई के अंत तक कच्चे तेल के उत्पादन में रिकॉर्ड कटौती जारी रखने को तैयार हो गए हैं, जिसके बाद सऊदी अरब ने ये फैसला लिया है। सऊदी अरब के इस फैसले से एशिया को झटका लगेगा, जो सऊदी अरामको सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी का सबसे बड़ा क्षेत्रीय बाजार है।

अब तक की सबसे बड़ी बढ़त

सऊदी अरब ने जून के मुकाबले जुलाई निर्यात के लिए अरब लाइट क्रूड के दाम 0.20 डॉलर प्रति बैरल बढ़ा कर 6.10 डॉलर प्रति बैरल कर दिए हैं। ब्लूमबर्ग की कैल्कुलेशन के मुताबिक सऊदी अरब द्वारा एशियाई ग्राहकों को बेचे जाने वाले अरब लाइट क्रूड में कीमत में महीने-दर-महीने आधार पर की गई ये सबसे बड़ी वृद्धि है। इससे भारत जैसे देशों का क्रूड ऑयल बिल बढ़ेगा, जो तेल के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। सरकार महंगे क्रूड के मद्देनजर पेट्रोलियम उत्पादों यानी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा सकती है।

सऊदी हर महीने बदलता है कीमत

सऊदी अरब अपने क्रूड को तेल बेंचमार्क के खास अंतर पर बेचता है। ये ग्लोबल रिफाइनर्स से चार्ज कर रहे प्रीमियम या डिस्काउंट में हर म हीने बदलाव करता है। आधिकारिक बिक्री मूल्य फिजिकल ऑयलम मार्केट में टोन सेट करने में मदद करता है, जहां असल बैरल में कारोबार होता है। इस बीच ग्लोबल तेल की कीमतों में अप्रैल में जितनी गिरावट आई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। सोमवार की सुबह ब्रेंट क्रूड, तेल की कीमतों के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क, 43.41 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ गया, जो 6 मार्च के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। ओपेक, रूस और इनके सहयोगियों द्वारा उत्पादन में प्रति दिन 9.7 मिलियन बैरल की कटौती के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत अप्रैल की शुरुआत से लगभग दोगुनी हो गई है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

ओपेक, संबद्ध देशों ने एक करोड़ बैरल प्रतिदिन की कटौती को एक महीने और बढ़ाया

दुबई। एजेंसी

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और उससे संबद्ध देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में करीब एक करोड़ बैरल प्रतिदिन की कटौती को जुलाई अंत तक एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यह कदम कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर बाजार में स्थिरता लाने की उम्मीद में उठाया गया है। ओपेक से संबद्ध देशों और रूस की अगुवाई में इससे बाहर के देशों की शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में यह फैसला किया गया। इस कदम का मकसद अधिशेष उत्पादन को कम करना, कीमतों में आ रही गिरावट को थामना है। वैश्विक स्तर पर विमानन सेवाएं इस महामारी की वजह से अब भी लगभग ठप हैं, जिससे कच्चे तेल की मांग प्रभावित हुई है। उत्पादन में कुल कटौती वैश्विक स्तर पर आपूर्ति का करीब दस प्रतिशत बैठती है। हालांकि, कई देशों ने लॉकडाउन में अब ढील दी है लेकिन कच्चे तेल के बाजार में जोखिम कायम है। ओपेक के अध्यक्ष एवं अल्जीरिया के पेट्रोलियम मंत्री मोहम्मद अरकब ने चेताया कि इस साल के मध्य तक वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का भंडारण बढ़कर 1.5 अरब बैरल पर पहुंच जाएगा। अरकब ने कहा कि इस दिशा में आज की तारीख तक हुई प्रगति के बावजूद हम अभी अपने प्रयासों में ढील नहीं दे सकते। सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री अब्दुलअजीज बिन सलमान ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि आज हम जहां पहुंचे हैं उसके लिए सभी ने प्रयास किया है। सलमान ने कहा कि अप्रैल में जिस दिन अमेरिका का तेल वायदा शून्य से नीचे आया था, तो उन्हें काफी झटका लगा था।

भारत की वृद्धि में 5 प्रतिशत की गिरावट होगी वित्तीय प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं: एस एंड पी

नयी दिल्ली। एजेंसी

साख निर्धारण से जुड़ी एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 5 प्रतिशत की गिरावट आने की आशंका है। उसने यह भी कहा कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत के बराबर वित्तीय प्रोत्साहन वृद्धि को थामने और उसे गति देने के लिये पर्याप्त नहीं है। एस एंड पी ने उभरते बाजारों पर एक रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस संकट से सेवा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चूंकि इसमें नियोक्ताओं की काफी संख्या है, अतः बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गयी हैं। उसने कहा, ''प्रवासी मजदूर भौगोलिक रूप से विस्थापित हुए हैं और हमारा अनुमान है कि इस प्रक्रिया के थमने में कुछ समय लगेगा। इस दौरान आपूर्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल असर रहेगा।'' रेटिंग एजेंसी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत की गिरावट आएगी। हालांकि अगले वित्त वर्ष 2021-21 में इसमें तेजी आएगी और इसके 8.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। वहीं 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2019-20 में 4.2 प्रतिशत रही जो 11 साल का न्यूनतम स्तर है। एस एंड पी ने कहा, ''रिजर्व बैंक ने फरवरी से नीतिगत दर में 1.15 प्रतिशत की कमी की है लेकिन इसको लेकर आकर्षण नहीं है क्योंकि बैंक कर्ज देने को इच्छुक नहीं हैं। वहीं सरकार ने जो वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है, वह जीडीपी का केवल 1.2 प्रतिशत है। यह आर्थिक वृद्धि को थामने और उसे गति देने के लिये पर्याप्त नहीं है।'' इससे पहले, रेटिंग एजेंसी फिच और क्रिसिल ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान जताया है जबकि मूडीज ने अर्थव्यवस्था में 4 प्रतिशत की कमी की आशंका जतायी है। सरकार ने पिछले महीने 20.97 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की जिसमें आरबीआई से मिला नकदी समर्थन शामिल हैं। इससे पहले, एस एंड पी ने कहा था कि सरकार का प्रोत्साहन पैकेज जीडीपी का 10 प्रतिशत नहीं है। सरकार ने सीधे तौर पर जो वित्तीय पैकेज दिया है वह जीडीपी का केवल 1.2 प्रतिशत है। शेष 8.8 प्रतिशत पैकेज में नकदी समर्थन उपाय और कर्ज गारंटी शामिल है जिससे वृद्धि को सीधे तौर पर मदद नहीं मिलेगी।

S&P Global Ratings

सऊदी अरब ने बढ़ाए कच्चे तेल के दाम

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सऊदी अरब को होगा फायदा

ओपेक, रूस और बाकी तेल उत्पादक देशों ने जुलाई के अंत तक 10 फीसदी कम ग्लोबल सप्लाई बरकरार रखने पर सहमति जताई है। टाइट सप्लाई और तेल की कीमतों में वृद्धि से सऊदी अरब को कोरोना के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी। दरअसल दुनिया में तेल के प्रमुख उपभोक्ता देशों में लॉकडाउन की घोषणा से अप्रैल में तेल की कीमतें सिंगल डिजिट में पहुंच गई थीं। जबकि सऊदी अरब लगभग 60 प्रतिशत राजस्व अभी भी तेल से हासिल करता है और कम कीमतों के कारण इसकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है। सऊदी अरब के तेल निर्यात की वैल्यू पहली तिमाही जनवरी-मार्च में सालाना आधार पर 21.9 प्रतिशत गिर कर 40 अरब डॉलर रह गई थी। चीन 2020 के पहले 3 महीनों में सऊदी के निर्यात के लिए मुख्य देश रहा। इसके बाद जापान और फिर भारत का नंबर है।

बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत, डेनमार्क के बीच समझौता

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये सहमति पत्र (एमओयू) पर दस्तखत किये हैं। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो एमओयू के तहत उसके ब्योरे के क्रियान्वयन पर काम करेगा। बयान के अनुसार बिजली मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा, उपयोगी सेवाओं और जलवायु मामलों के मंत्रालय के बीच

एमओयू पर हस्ताक्षर पांच जून को किये गये। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। सहमति पत्र पर भारत की तरफ से बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की तरफ से यहां डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने हस्ताक्षर किये। समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों सहयोग की बात कही गयी है। इन क्षेत्रों में डेनमार्क के साथ सहयोग से देश के बिजली बाजार को लभ होगा। इन पहचाने गये क्षेत्रों में सहयोग को हकीकत में बदलने के लिये एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा। इस समूह की सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे और वे दोनों तरफ से सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति को रिपोर्ट करेंगे।

नीति आयोग का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की पुनः ब्रांडिंग कर 'अश्मि' नाम देने का सुझाव

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाले एक कार्यकारी समूह ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की फिर से ब्रांडिंग (री-ब्रांडिंग) करने का सुझाव दिया है। साथ ही देश में विरासत एवं स्मारकों के प्रबंधन की कार्ययोजना भी सौंपी है। समूह ने अपनी रपट में देश के विरासत स्थलों की ब्रांडिंग टैगलाइन को पर्यटन टैगलाइन 'अतुल्नीय भारत' के साथ जोड़ने का सुझाव दिया है। 'अतुल्नीय भारत' की पहले से एक मजबूत पहचान है। इसी के साथ पुरातत्व विभाग के ढांचे का विस्तार करने का भी सुझाव दिया गया है। इसके लिए कई नए नाम भी सुझाए गए हैं जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं विरासत प्रबंधन विभाग (अश्मि) प्रमुख है। हिंदी में अश्मि का अर्थ 'स्वाभिमान, मजबूत और पत्थर से जन्मा' होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार पिछले साल इस कार्यकारी समूह का गठन किया गया था। समूह को 'भारत में विरासत प्रबंधन को बेहतर बनाने' से जुड़े सुझाव देने थे।

एचपीसीएल की विजग रिफाइनरी के 3 अरब डॉलर की विस्तार योजना में

मजदूरों की कमी और मानसून के कारण देरी

नई दिल्ली। एजेंसी

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने विशाखापट्टनम रिफाइनरी के विस्तार की समय सीमा को आगे बढ़ाकर कम से कम अक्टूबर-नवंबर कर दिया है। यह जानकारी कंपनी के एक सूत्र ने दी। उन्होंने कहा कि मजदूरों की कमी और मानसून के आगमन के कारण विस्तार की योजना को फिलहाल टालना पड़ा है। विशाखापट्टनम रिफाइनरी के विस्तार पर 209.28 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकारी तेल रिफाइनिंग कंपनी ने पहले विस्तार का काम जुलाई में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा था। विशाखापट्टनम रिफाइनरी के विस्तार पर 209.28 अरब रुपए (2.77 अरब डॉलर) खर्च होने का अनुमान है। विस्तार के बाद समुद्र तटीय रिफाइनरी की क्षमता बढ़कर करीब दोगुना हो जाने का अनुमान है।

लॉकडाउन के कारण जो काम मानसून से पहले पूरा हो जाना था, वो नहीं हो पाया

सूत्र ने कहा कि कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण बहुत सारे मजदूर अपने पैतृक गांव या शहर चले गए हैं। दूसरी ओर मानसून के आगमन के कारण निर्माण कार्य को जारी रख पाना कठिन हो गया है। लॉकडाउन के कारण जो काम हमें मानसून से पहले पूरे कर लेने थे, वो हम नहीं कर पाए। यह अवसर हाथ से निकल गया।

कोरोनावायरस महामारी से पहले की गतिविधियों को फिर से चालू करने में कुछ वक्त लगेगा

हमने नई स्थिति की समीक्षा नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है कि परियोजना को पूरा होने में कम से कम अक्टूबर-नवंबर तक का समय लग जाएगा। एचपीसीएल ने इस विषय पर हालांकि कोई टिप्पणी नहीं की है। सरकार ने लॉकडाउन में काफी ढील दे दी है। लेकिन कोरोनावायरस महामारी से पहले की गतिविधियों को फिर से चालू करने में कुछ वक्त लगेगा। क्योंकि अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं अब भी बंद हैं और वायरस संक्रमण अब भी फैल रहा है।

सूरक्षा के लिए मानसून में निर्माण और मिकैनिकल कार्य रोक दिए जाते हैं

सूत्र ने कहा कि सूरक्षा को ध्यान में रखते हुए मानसून के दौरान निर्माण और मिकैनिकल कार्य आमतौर पर बंद कर दिए जाते हैं। चार महीने का मानसून सत्र जून में शुरू होता है। इस साल यह पहली जनवरी को केरल में पहुंच चुका है।

रिफाइनरी में एक छोटी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को बदला जाना है

विस्तार योजना के तहत आंध्र प्रदेश की इस रिफाइनरी में एक छोटी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को बदलकर उसकी जगह 1.8 लाख बैरल रोजाना वाली यूनिट लगाई जाएगी। कंपनी कुछ अन्य यूनिट का भी निर्माण कर रही है, जिनमें 3.52 लाख टन सालाना वाली नाप्था आइसोमराइजेशन यूनिट, 30.53 लाख टन सालाना वाली हाइड्रोक्रैकर और एक बिजली घर शामिल है। यह बिजली घर नाप्था या प्राकृतिक गैस दोनों पर चल सकती है।

कुछ यूनिट्स की क्षमता बढ़ाई जानी है

परियोजना के तहत कुछ यूनिट्स की क्षमता भी बढ़ाई जानी है। इसके तहत नाप्था हाइड्रोट्रीटर की क्षमता 30 फीसदी बढ़ाकर 15 लाख टन सालाना की जानी है। डीजल हाइड्रोट्रीटर की क्षमता 30 फीसदी बढ़ाकर 28.6 लाख टन सालाना की जानी है। साथ ही कंटीनुअस कैटेलिटिक क्रैकर की क्षमता बढ़ाकर 10.39 लाख टन सालाना की जानी है।

सरकार 15 प्रतिशत कंपनी कर दर का लाभ लेने की समयसीमा बढ़ाने पर करेगी विचारः वित्त मंत्री

नयी दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी को देखते हुए नये निवेश पर 15 प्रतिशत की घटी दर से कंपनी कर का लाभ लेने की समयसीमा बढ़ाने पर विचार करेगी। सरकार ने निजी निवेश आकर्षित करने और धीमी पड़ती आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिये पिछले साल सितंबर में कंपनी कर की दरों में 10 प्रतिशत तक की कटौती की। यह 28 साल में सबसे बड़ी कटौती की गई। इसके तहत मौजूदा कंपनियों के लिये मूल कंपनी कर की दर को 30 प्रतिशत से कम कर 22 प्रतिशत और एक अक्टूबर 2019 के बाद गठित और 31 मार्च 2023 से पहले परिचालन शुरू करने वाली नई विनिर्माण इकाइयों के लिये कंपनी कर की दर को 25 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत कर दिया गया। सीतारमण ने कहा, ''मैं देखूंगी कि क्या किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि उद्योग नये निवेश पर 15 प्रतिशत कंपनी कर का लाभ उठाये और मैं 31 मार्च 2023 की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर गौर करूंगी।''

उद्योग मंडल फिक्की के सदस्यों को संबोधित करते हुए मंत्री ने अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार के लिये उद्योग को हर संभव सरकारी

सहायता का आश्वासन दिया। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 आपात ऋण सुविधा केवल सूक्ष्म, लघु एवं मझोली कंपनियों के लिये ही नहीं है बल्कि सभी कंपनियां इसके दायरे में आतीं हैं। नकदी से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ''हमे इस मसले का स्पष्ट रूप से समाधान किया है। निश्चित रूप से नकदी की उपलब्धता है। अगर कोई मसला रहता है, हम उस पर गौर करेंगे।'' वित्त मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभागों से बकाये का निपटान करने को कहा गया है और अगर किसी विभाग से जुड़ा कोई मुद्दा रहता है, सरकार उस पर ध्यान देगी।

उन्होंने उद्योगों से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या सेबी की समयसीमा से संबद्ध अपनी सिफारिशें देने को कहा ताकि उसको लेकर जरूरी कदम उठाये जा सके। कोरोना संकट से प्रभावित क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के संदर्भ में सीतारमण ने कहा, ''माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर में कटौती का मामला परिषद में जाएगा। लेकिन जीएसटी परिषद राजस्व पर भी ध्यान दे रही है। किसी भी क्षेत्र के लिये जीएसटी दर में कटौती का निर्णय परिषद को करना है।'' राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने फिक्की सदस्यों से कहा कि कंपनियों के आयकर रिफंड का काम शुरू हो गया है। आयकर विभाग ने पिछले कुछ सप्ताह में 35,000 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।

MSMEs को पांच दिनों में बांटे गए 8,320 करोड़ रुपये के कर्ज

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public sector banks) ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Schemes) के तहत पांच जून तक एमएसएमई को 8,320 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे हैं। एक जून से शुरू शत प्रतिशत गारंटी वाली इस योजना के तहत सरकारी बैंकों ने 17,705.64 करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज में हुई थी घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (MSMEs) के लिये घोषित तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना है।

5 जून तक 17705 करोड़ लोन को मंजूरी

सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा, 'पांच जून 2020 तक सरकारी बैंकों ने 100 प्रतिशत आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 17,705.64 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है। इनमें से 8,320.24 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया गया है।'

SBI ने 11701 करोड़ मंजूर किए

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने इस दौरान 11,701 करोड़ रुपये के कर्ज मंजूर किये हैं, जबकि लगभग 6,084.71 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे हैं। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 1,295.59 रुपये के कर्ज की मंजूरी दी है, और 242.92 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया है। मंत्रिमंडल ने एमएसएमई क्षेत्र के लिये आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को 21 मई को मंजूरी दी थी।

लोन को NCGTC से गारंटी कवरेज

इस योजना के तहत पात्र MSMEs और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिये नैशनल ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (NCGTC) के द्वारा 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान की जायेगी। इसके लिये सरकार के द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष और अगले तीन वित्त वर्ष के दौरान 41,600 करोड़ रुपये मुहैया कराये जायेंगे।

'शून्य' जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों के लिये एसएमएस सेवा, 22 लाख करदाताओं को होगा फायदा

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने शून्य मासिक जीएसटी (माल एवं सेवा कर) रिटर्न भरने वाले करदाताओं के लिये एसएमएस (शार्ट मैसेजिंग सर्विस) सेवा शुरू की। इससे करीब 22 लाख पंजीकृत करदाताओं को लाभ होगा।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक बयान में कहा, ''करदाताओं की सुविधा के लिये बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सोमवार से उन्हें एसएमएस के जरिये जीएसटीआर-3बी फार्म में शून्य जीएसटी मासिक रिटर्न भरने की अनुमति दे दी है।''इससे 22 लाख पंजीकृत करदाताओं के लिये जीएसटी का अनुपालन करना सरल होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें साझा पोर्टल पर अपने एकाउंट पर 'लॉग इन' करना होता और उसके बाद हर महीने रिटर्न फाइल करना होता।शून्य रिटर्न आगामी महीने की पहली तारीख को 14409 पर एसएमएस- कर भेजा जा सकता है। इस

सुविधा के तहत जिन इकाइयों का फार्म जीएसटी-3बी में सभी सारणी में शून्य या कोई 'एंट्री' नहीं है, वे पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर एसएमएस के जरिये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उक्त रिटर्न का सत्यापन पंजीकृत मोबाइल नंबर आधारित वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सुविधा के जरिये होगा। सीबीआईसी ने कहा कि जिन करदाताओं की देनदारी शून्य है, उन्हें जीएसटी पोर्टल पर 'लॉग ऑन' करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में नया नियम पिछले महीने पेश किया था। इसके तहत शून्य रिटर्न एसएमएस सुविधा के जरिये भरने की अनुमति करदाताओं को दी गयी थी। सीबीआईसी ने कहा, ''जीएसटीएन पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से शून्य फार्म जीएसटीआर-3बी भरने के तरीके के बारे में जानकारी उपलब्ध है...।'' माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 1.22 करोड़ इकाइयां पंजीकृत हैं।

शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद, सेंसेक्स में 290 अंकों की बढ़त, 10,116 के स्तर पर क्लोज हुआ निफ्टी

मुंबई। दिनभर उतार-चढ़ाव के बीच आखिरकार शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 290 अंकों की बढ़त के साथ 34,247.05 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी ने भी 69.50 (0.69%) अंकों की तेजी के साथ 10,116.15 के स्तर पर दिन के कारोबार समाप्त किया।

प्राइमरी स्कूल पैरंट एसोसिएशन का गठन

कोरोना काल में उत्पन्न समस्याओं को हल करना उद्देश्य

इंदौर। कोरोना संक्रमण के दौरान जिस प्रकार से प्राइमरी शिक्षा प्रभावित हुई है और प्राइमरी शिक्षा के बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं को मंच प्रदान करने के लिए प्राइमरी स्कूल पैरंट एसोसिएशन का गठन किया गया है। संस्था का मुख्य उद्देश्य वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्राइमरी स्कूल एवं प्राइमरी विद्यार्थियों के आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देकर कोरोना काल में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना है। एसोसिएशन में सर्वसम्मति से संतोष वाधवानी को अध्यक्ष एवं शिशुभ अग्रवाल को सचिव मनोनीत किया गया है। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के लिए मोनू जायसवाल एवं कमल छाबड़ा , सह-सचिव शेखर चौधरी एवं कोषाध्यक्ष पद पर जितेंद्र सिंह चौहान का मनोनयन किया गया है।

देश हुआ अनलॉक तो दोगुने से अधिक हो गई पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना संकट के कारण 25 मार्च से 31 मई तक देश में लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप पड़ी थीं। चौथे लॉकडाउन में ढील मिली तो आर्थिक गतिविधियों ने गति पकड़ ली। इसी के साथ देश में पेट्रोल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग लॉकडाउन के शुरुआती दिनों की तुलना में दोगुने से अधिक हो गई है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बुधवार को बताया कि इस साल अप्रैल के मुकाबले मई में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग दोगुनी हो गई थी तथा जून में इसमें और वृद्धि हुई है। बढ़ी मांग को देखते हुये कंपनी ने अपने तेल शोधन संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाकर क्षमता का 83 प्रतिशत कर दिया।

पेट्रोल की मांग 70 और डीजल की 59 फीसद बढ़ी

इंडियन ऑयल का कहना है कि अप्रैल के मुकाबले मई में लगभग सभी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में तेज इजाफा हुआ। पेट्रोल की मांग 70 फीसदी और डीजल की 59 फीसदी बढ़ी। कंपनी रोजाना 25 लाख रसोई गैस सिलिंडर रीफिल कर रही है और सिलिंडर की डिलिवरी में औसत बैकलॉग एक दिन से भी कम रह गया है हालांकि विमान ईंधन की मांग अब भी सामानय दिनों के मुकाबले 24 प्रतिशत कम है। लॉकडाउन के आरंभिक चरण में मांग काफी कम रह गई थी। इसे देखते हुये अप्रैल के आरंभ में इंडियन ऑयल ने उत्पादन घटाकर 39 प्रतिशत पर सीमित कर दिया था। लॉकडाउन के दूसरे चरण में आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी बहुत छूट दिए जाने से मई के आरंभ में उत्पादन बढ़कर 55 प्रतिशत पर पहुंच गया। मई के अंत तक उसने अपना उत्पादन 78 प्रतिशत कर दिया था जिसे अब और बढ़ाकर 83 फीसदी कर दिया गया है। कंपनी ने बताया कि गुवाहाटी संयंत्र में रखरखाव का काम पूरा हो गया है। इससे इस महीने 90 प्रतिशत क्षमता पर उत्पादन शुरू हो जायेगा।

बांस पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने मंगलवार को बांस पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया। इसका मकसद अगरबत्ती विनिर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा, ''अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।''आदेश के मुताबिक व्यापारियों समेत किसी के भी बांस आयात करने पर एक समान दर से 25 प्रतिशत का आयात शुल्क लगेगा। यह कदम स्थानीय बांस किसानों को लाभ प्रदान करेगा। साथ ही अगरबत्ती उत्पादन में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को भी फायदा होगा, क्योंकि पहले केवल बड़े अगरबत्ती विनिर्माता ही कम कीमतों पर बांस का आयात करने में सक्षम थे।

भारत ने मलेशिया से आयातित कैलकुलेटर पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत ने मलेशिया से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। यह कदम घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से संरक्षण देने के लिए उठाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने जांच के बाद मलेशिया से आयातित कैलकुलेटरों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। राजस्व विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि कैलकुलेटर पर 0.92 डॉलर प्रति इकाई का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। यह पांच साल तक लागू रहेगा। डीजीटीआर ने अपनी जांच में पाया कि मलेशिया से कैलकुलेटर का आयात सामान्य कीमत से कम पर हो रहा है। इससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है और यह डंपिंग का मामला बनता है। डीजीटीआर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। इस पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय लेता है। अजंता एलएलपी ने मलेशिया से आयातित कैलकुलेटर पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने को आवेदन किया था। दोनों देशों के बीच 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 17.25 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 14.71 अरब डॉलर था।

SBI 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेगा वार्षिक आम बैठक

मुंबई। एजेंसी

देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एँ) 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी वार्षिक आम सभा करेगा। बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने कोविड-19 संकट को देखते हुए यह निर्णय किया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अप्रैल में कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी वार्षिक आम सभा करने की अनुमति दे दी थी। एसबीआई ने विज्ञप्ति में कहा कि विभिन्न हितधारकों के अनुरोध के बाद यह निर्णय किया गया है। बैठक 17 जून को दोपहर तीन बजे से शुरू होगी। बैंक ने कहा है, 'शेयरधारकों को चार निदेशकों को चुनने के लिए ई-मत की अनुमति होगी। यह निदेशक पांच उम्मीदवारों की सूची में से चयनित किए जाएंगे। यह प्रक्रिया एसबीआई कानून और एसबीआई जनरल रेग्युलेशंस 1955 के तहत होगी।' बैंक ने कहा है कि सभी पक्षों की बेहतरी और लॉकडाउन के तहत लागू प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ माह से वह प्रमुख कार्यक्रमों में लोगों की भौतिक रूप से उपस्थिति से बच रहा है।

अनलॉक के बाद हाई रिस्क वाले 15 देशों में शामिल हो जाएगा भारतः स्टडी

नई दिल्ली। एजेंसी

एक जून से कोरोना लॉकडाउन (अनलॉक) खुलने के बाद से भारत उन 15 हाई रिस्क वाले देशों में शामिल हो सकता है, जहां लॉकडाउन में ढील देने से नए कोविड 19 के संक्रमणों में बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में कोरोना की ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें मामले हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। सुरक्षा रिसर्च फर्म नोमुरा ने कहा कि इस सब के कारण कड़े प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जा सकता है। 45 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने वाले विश्लेषण में लोगों की आवाजाही से संक्रमण की गति को देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि उपकरण से मिले जुले परिणाम सामने आए हैं।17 देशों ने संक्रमण की दूसरी लहर के संकेत के साथ अर्थव्यवस्था को खोला। 13 देश कुछ अस्थायी चेतावनी के संकेत दिखा रहे हैं और 15 देशों में एक दूसरी लहर का खतरा सबसे अधिक है। विश्लेषण में 45 देशों को तीन समूहों में विभाजित किया है- 'ट्रैक पर', 'चेतावनी संकेत' का सामना कर रहे हैं या 'खतरे के क्षेत्र' में। इंडोनेशिया, चिली और पाकिस्तान जैसे कई अन्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों के साथ भारत खतरे के क्षेत्र में आता है। इस समूह में कुछ अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे स्वीडन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा शामिल हैं। 'ट्रैक पर' में आने वालों में फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया हैं, जबकि जर्मनी, संयुक्त राज्य और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को 'जोखिम' का सामना करना पड़ रहा है। यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब इनमें से अधिकांश राष्ट्र लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं ताकि लोगों को काम करने के लिए वापस जाने की अनुमति मिल सके और कई क्षेत्रों में आमदनी और रोजगार को बचाया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों से आग्रह किया कि वे वायरस को रोकने के प्रयासों के साथ आगे बढ़ें।

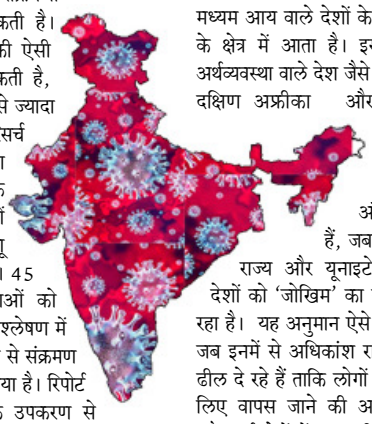

BOB के ग्राहक 20 दिन में करवा लें केवाईसी नहीं तो फ्रीज हो जाएगा अकाउंट

नई दिल्ली। एजेंसी

आप बैंक आफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) के ग्राहक हैं और आपने इस साल अभी तक केवाईसी (ख्ण्) नहीं करवाया है तो संभल जाएं। बैंक ने कहा है कि अगले 20 दिनों के अंदर जो ग्राहक अपना केवाईसी नहीं करवाएंगे, उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि आप अपने खाते से न तो पैसा निकाल पाएंगे और न ही कुछ और ट्रांजेक्शन (Tranjection) कर पाएंगे।

सभी ग्राहकों को भेज दिया है संदेश

बीओबी (BOB) के एक अधिकारी का कहना है कि बैंक की तरफ से भी ग्राहकों को संदेश भेज दिया गया है। उनसे कहा गया है कि अगले 20 दिनों के अंदर अपने खाते के लिए केवाईसी डॉक्युमेंट के साथ ही पैन नंबर (PAN), पैन नंबर नहीं होने पर फार्म 60 भर कर जमा करें। साथ ही खाताधारी को अपने जन्म तिथि (Date of Birth) की जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है।

इस तारीख से हो सकता है खाता फ्रीज

बैंक का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार वह अपने ग्राहकों से केवाईसी डिटेल अपडेट करने को कह रहे हैं। उनके जो ग्राहक निर्धारित अवधि में केवाईसी डिटेल देने में असफल रहेंगे, उनका खाता 1 जुलाई 2020 से फ्रीज किया जा सकता है।

केवाईसी में कौन सा डॉक्युमेंट चलेगा

केवाईसी करवाने के लिए ग्राहकों को अपने बैंक की शाखा में वोटर आईडी (Voter Id), आधार कार्ड (Aadhaar) या आधार संख्या वाली चिट्ठी, मनरेगा कार्ड, पासपोर्ट, नेशनल पोपुलेशन रजिस्टर की चिट्ठी आदि की फोटो कॉपी जमा कर सकते हैं।

ईपीएफओ ने अप्रैल-मई के दौरान 11,540 करोड़ रुपये के 36.02 लाख दावों के निपटान किये

नयी दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 'लॉकडउाउन' के दौरान पिछले दो महीनों में 36.02 लाख दावों के निपटान किये और अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपये वितरित किये। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सदस्यों के लिये चीजों को आसान बनाने के इरादे से ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को समय पर सेवा देने को लेकर हर संभव प्रयास किये।'' ईपीएफओ के अनुसार 'लॉकडाउन' की पाबंदियों के बावजूद ईपीएफओ ने अप्रैल-मई के दौरान 36.02 लाख दावों के निपटान किये और अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपे वितरित किये।

बयान में कहा गया है कि कुल दावों में से 15.54 लाख दावे कोविड-19 संकट से राहत देने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत ईपीएफ से पैसा निकालने की दी गयी अनुमति से संबद्ध थे। इसके तहत कुल 4,580 करोड़ रुपये वितरित किये गये। इन कठिन समय में ईपीएफओ सदस्यों खासकर जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है, उन्हें भविष्य निधि खाते से निकालने की अनुमति से बड़ी राहत मिली।कोरोना वायरस महामारी से राहत देने के लिये पीएमजीकेवाई के तहत अंशधारकों को तीन महीने का वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ते) या सदस्यों के खाते में जमा रकम का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी गयी थी। इससे कई कामगारों को राहत मिली।

आंकड़ों के अनुसार कुल दावाकर्ताओं में 74 प्रतिशत से अधिक वे लोग थे जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है। ईपीएफओ के अनुसार करीब 24 प्रतिशत दावा उन लोगों के थे जिनका वेतन 15,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच था। वहीं 50,000 रुपये से अधिक के वेतन वाली श्रेणी में दावा केवल 2 प्रतिशत रहा। बयान के अनुसार 'लॉकडाउन' के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ईपीएफओ ने 50 प्रतिशत से कम कर्मचारियों के साथ काम किया। कर्मचारियों की कमी के बावजूद दावों का निपटान समय पर किया गया। कोरोना संकट से निपटने के लिये किये गये दावों के निपटान करीब 10 दिन से कम कर लगभग 3 दिन में किये गये।

कीटनाशक रसायन उद्योग संगठन पीएमएफआई ने 27 कीटनाशकों पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

कीटनाशक कंपनियों के संगठन पीएमएफएआई ने देश में 27 कीटनाशक रसायनों के कारोबार पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया । संगठन का कहना है कि इससे 6,000 करोड़ मूल्य का कारोबार खत्म हो जाएगा, किसानों के लिए कीटनाशक महंगे हो जाएंगे, भारत से कीटनाशकों का निर्यात प्रभावित होगा और इसका लाभ चीन जैसे देशों की कंपनियों को होगा। इतना ही नहीं किसानों के हित प्रभावित होंगे क्योंकि जो विकल्प हैं, वो चार गुना महंगे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को वीडिया कांफ्रेस के जरिए पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि पर्यावरण से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों पर मधुमक्खी की हानि और कैंसर आदि कहा हौवा खड़ा कर कीटनाशक उद्योग पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने हाल ही में गजट अधिसूचना का मसौदा जारी किया जिसमें 27 प्रकार के कीटनाशक रसायनों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इस बारे में संबंधित पक्षों से अगले 45 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया मांगी गयी है। पेस्टिसाइड मैनुफैक्चरर्स एंड फार्मुलेटर्स एसोसएिशन ऑफ इंडिया (पीएमएफएआई) के अध्यक्ष प्रदीप दवे ने वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये संवाददाताओं से कहा, ''हम इस मामले में उच्च अधिकार प्राप्त वैज्ञानिकों की समिति से जांच चाहते हैं।'' उन्होंने कहा कि 27 कीटनाशकों पर पाबंदी का प्रस्ताव मेक इन इंडिया और आत्म निर्भर भारत की भावना तथा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन के खिलाफ है। दवे ने कहा, ''इन 27 जेनेरिक कीटनाशकों का कुल बाजार 6,000 करोड़ रुपये का है। इसमें से 4,000 करोड़ रुपये घरेलू बिक्री और 2,000 करोड़ रुपये का निर्यात होता है। हम पूरे कारोबार से हाथ धो बैठेंगे।'' घरेलू कीटनाशक उद्योग का बाजार 40,000 करोड़ रपये का हैं इसमें से करीब 18,000 करोड़ रुपये की घरेलू बिक्री है। दवे ने कहा कि जेनेरिक कीटनाशकों का वैश्विक बाजार 30,000 करोड़ रुपये का है और इस पर पूरी तरह से चीन का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने तैयार कृषि औषधियों पर कम से कम पंद्रह प्रतिशत की दर से आयात शुल्क लगाने की भी मांग की। प्रमुख कंपनी यूपीएल लि. के चेरमैन राजू श्रॉफ ने कहा कि देश विभिन्न कृषि खाद्य पदार्थों का प्रमुख उत्पादक देश है लेकिन अमेरिका समेत कई बड़े देशों की तुलना में कीटनाशकों की खपत कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण से जुड़े गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कीटनाशक उद्योग के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और लोगों तथा संबद्ध पक्षों को गुमराह कर रहे हैं। श्रॉफ ने आरोप लगाया कि इन एनजीओ को विदेशी एजेंसियों से पैसा मिलता है ओर वे भारतीय किसानों तथा घरेलू उद्योग के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों की चिंता की जांच आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के वैज्ञानिकों द्वारा की जानी चाहिए। श्रॉफ ने कहा कि अगर इन 27 कीटनाशकों पर पाबंदी लगायी जाती है तो इसका कृषि उपज, खेती की लागत और किसानों की आय पर असर पड़ेगा।

MSME को सपोर्ट देने के लिए फाइनेंस कंपनियों में विदेशी निवेश बढ़ाने की जरूरत- गडकरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाया जा सकता है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक बड़ा समर्थन साबित होगा। दरअसल एनबीएफसी के पास निवेश के रूप में पैसा आएगा, जिसे वे एमएसएमई को लोन के रूप में देंगी। इससे एनबीएफसी और एमएसएमई दोनों सेक्टरों को फायदा हो सकता है। गडकरी ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एमएसएमई को समर्थन देने के लिए एनबीएफसी, राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी बैंकों, क्रेडिट सोसायटी आदि को मजबूत करना आवश्यक है।

क्या होगा फायदा

रिपोर्ट के अनुसार गडकरी ने आधिकारिक बयान में कहा है कि एनबीएफसी को मजबूत करने के लिए एफडीआई को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे एमएसएमई को अधिक सहारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी के लिए एक क्रेडिट रेटिंग सिस्टम भी तैयार किया जा सकता है। उनके मुताबिक एनबीएफसी सेक्टर में विदेशी निवेश हासिल करने के लिए संभावना को तलाशने की जरूरत है। गडकरी के अनुसार किसी एनबीएफसी की रेटिंग अच्छी है तो यह बेहतर हो सकता है ऐसी कंपनी विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके। लेकिन इसके लिए मापदंड तय किए जाने चाहिए।

एमएसएमई का जीडीपी में कितना है योगदान

इस समय भारत में लगभग 6.34 करोड़ एमएसएई इकाइयाँ हैं, जो विनिर्माण जीडीपी में लगभग 6.11 फीसदी और सर्विस जीडीपी में करीब 24.63 फीसदी योगदान करती हैं। वहीं देश के विनिर्माण उत्पादन में इनका योगदान 33.4 फीसदी। ये 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान करती हैं। इसीलिए सरकार इस सेक्टर के लिए लगातार उपाय कर रही है। पिछले महीने भी 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में से एमएसएमई को काफी कुछ दिया गया। इतना ही नहीं सरकार ने एमएसएमई को तरह के नियमों में भी ढील दी है। सरकार ने एमएसएमई का विस्तार करने के लिए इसकी परिभाषा में भी बदलाव कर दिया है।

कोविड-19 संकट के चलते इस साल 4.9 करोड़ अतिरिक्त लोगों के अत्यंत गरीब होने की आशंका : संरा प्रमुख

संयुक्तराष्ट्र। एजेंसी

कोविड-19 संकट की वजह से इस साल करीब 4.9 करोड़ और लोग अत्यंत गरीबी के गर्त में जा सकते हैं। इतना ही नहीं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हर एक प्रतिशत की गिरावट का असर लाखों बच्चों के विकास को अवरुद्ध करेगा। यह अंदेशा संयुक्तराष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने जताया है। उन्होंने देशों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है। गुतारेस ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो साफ है कि भीषण वैश्विक खाद्यान्न आपात स्थिति का जोखिम बढ़ रहा है। इसका दीर्घावधि में करोड़ों बच्चों और युवाओं पर असर हो सकता है। खाद्य सुरक्षा पर एक नीति जारी करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया की 7.8 अरब आबादी को भोजन कराने के लिए पर्याप्त से अधिक खाना उपलब्ध है। लेकिन वर्तमान में 82 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी का शिकार हैं। और पांच वर्ष की आयु से कम के करीब 14.4 करोड़ बच्चों का भी विकास नहीं हो है। हमारी खाद्य व्यवस्था ढह रही है और कोविड-19 संकट ने हालात को बुरा बनाया है।'' गुतारेस ने कहा, ''इस साल कोविड-19 संकट के चलते करीब 4.9 करोड़ और लोग अत्यंत गरीबी का शिकार हो जाएंगे। खाद्य और पोषण से असुरक्षित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैश्विक जीडीपी में प्रत्येक प्रतिशत की गिरावट सात लाख अतिरिक्त बच्चों के विकास को अवरुद्ध करेगी। उन्होंने कहा कि प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न वाले देशों में भी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। गुतारेस ने 'तत्काल कार्रवाई' करने की बात को दोहराया, ताकि इस महामारी के सबसे बुरे वैश्विक परिणामों को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने देशों से लोगों की जिंदगी और आजीविका बचाने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि देशों को उन जगहों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है जहां सबसे ज्यादा जोखिम है। उन्होंने कहा , ''इसका मतलब यह है कि देशों को खाद्य और पोषण सेवाओं को अनिवार्य कर देना चाहिए जबकि खाद्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए।''

हींग, केसर की पैदावार को बढ़ावा देने के प्रयास

टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना होगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश की प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था सीएसआईआर की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई आईएचबीटी ने हींग और केसर की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। यह जानकारी मंगलवार को एक सरकारी विज्ञप्ति में दी गयी। विज्ञप्ति के अनुसार केसर और हींग का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संगठन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद(आईसीएआर) की हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी (सीएसआईआर-आईएचबीटी) ने हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ हाथ मिलाया है। यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने में मददगार हो सकती है। सीएसआईआर-आईएचबीटी के निदेशक डॉ संजय कुमार ने कहा है, 'इन फसलों की पैदावार बढ़ती है तो इनके आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। सीएसआईआर-आईएचबीटी किसानों को इसके बारे में तकनीकी जानकारी मुहैया कराने के साथ-साथ राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों एवं किसानों को प्रशिक्षित भी करेगा। राज्य में केसर और हींग के क्रमशः घनकंद और बीज उत्पादन केंद्र भी खोले जाएंगे।'केसर और हींग दुनिया के सबसे मूल्यवान मसालों में गिने जाते हैं।

भारतीय व्यंजनों में सदियों से हींग और केसर का व्यापक रूप से उपयोग होता रहा है। भारत में,केसर की वार्षिक माँग करीब 100 टन है, लेकिन हमारे देश में इसका औसत उत्पादन लगभग 6-7 टन ही होता है। इस कारण हर साल बड़ी मात्रा में केसर का आयात करना पड़ता है। इसी तरह,भारत में हर साल 600 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 1200 टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से आयात करनी पड़ती है। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में करीब 2,825 हेक्टरेयर क्षेत्र में केसर की खेती होती है।

सीएसआईआर-आईएचबीटी ने केसर उत्पादन की तकनीक विकसित की है, जिसका उपयोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के गैर-परंपरागत केसर उत्पादक क्षेत्रों में किया जा रहा है। संस्थान में रोग-मुक्त घनकंद के उत्पादन के लिए टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल भी विकसित किए गए हैं। सीएसआईआर-आईएचबीटी ने नयी दिल्ली स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीपीजीआर) की मदद से हींग से संबंधित छह पादप सामग्री पेश की हैं, और उसके उत्पादन की पद्धति को भारतीय दशाओं के अनुसार मानक रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। हींग एक बारहमासी पौधा है और यह रोपण के पांच साल बाद जड़ों से ओलियो-गम राल का उत्पादन करता है। इसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र की अनुपयोगी ढलान वाली भूमि में उगाया जा सकता है। इस पहल के शुरू होने बाद इन दोनों फसलों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अत्याधुनिक टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की जाएगी।

डॉ कुमार ने कहा है कि परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तकनीकी सहायता के अलावा केसर उत्पादन क्षेत्रों की निगरानी और किसानों के लिए अन्य क्षेत्रों के दौरे भी आयोजित किए जाएंगे। अगले पांच वर्षों में राज्य में कुल 750 एकड़ भूमि इन फसलों के अंतर्गत आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के निदेशक डॉ आर.के. कौंडल ने कहा है कि यह परियोजना किसानों की आजीविका में वृद्धि करने के साथ-साथ राज्य और देश को लाभान्वित करने में मददगार हो सकती है।

दूर्वा से भी प्रसन्न होते हैं गजानन

सर्वविदित है कि पूजन में सर्वप्रथम श्रीगणेश की पूजन का विधान है। शास्त्रों में विधिपूर्वक बताया गया है कि भगवान श्रीगणेश के पूजन के बगैर किसी भी देवी या देवता का पूजन करने से लाभ न के बराबर मिलता है।

ऐसी मान्यता है कि महादेव के त्रिशूल से पार्वती नंदन श्रीगणेश का मस्तक जब कट गया तब देवी शिवा क्रोधित हो गईं तथा उन्होंने अनेक शक्तियों को उत्पन्न करके प्रलय मचाने की आज्ञा दे दी। उन परम तेजस्वी शक्तियों ने सर्वत्र संहार करना प्रारंभ किया। देवगण हाहाकार करने लगे। तब शिव जी के आदेश से देवताओं ने हाथी का सिर लाकर शिवा पुत्र के धड़ से जोड़ दिया। महेश्वर के तेज से पार्वती का प्रिय पुत्र जीवित हो गया।

भगवान शिव एवं देवी पार्वती के साथ ही समस्त देवगण ने पार्वतीनंदन श्रीगणेश को आशीर्वाद स्वरूप अनेक वरदान प्रदान किए। भगवान शिव ने श्रीगणेश को विघ्न विनाशक के रूप में अध्यक्ष घोषित कर दिया। तभी से पूजा में श्रीगणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है अर्थात किसी भी देवी-देवता की पूजा से पहले श्रीगणेश की पूजा यदि न की जाए तो देवी-देवता के पूजन से लाभ प्राप्त नहीं होता।

भगवान शिव चारों ओर विराजमान हैं। व्रत की विधि बताते हुए महादेव ने भक्तिपूर्वक गजमुख को प्रसन्न करने के लिए किए गए व्रत उपवास एवं पूजन की महिमा का गान किया तथा कहा कि जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा तथा उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्गों के लोगों विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। सदा विजय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अनिवार्य कर्त्तव्य है। भक्त जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अत: जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे तुम्हारी सेवा अवश्य करनी चाहिए।

गणेश पुराण में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्नकाल में भी आदिदेव गणेश के पूजन का महत्व बताया गया है। कथा इस प्रकार है गणेश दर्शन की तीव्र लालसा से शिवाप्रिया लेखनाद्रि के एक रमणीय स्थान पर गणेश का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगीं। इस प्रकार 12 वर्षों तक कठोर तप करने पर गुणवल्लभ गणेश संतुष्ट हुए और पार्वती के सम्मुख प्रकट होकर उन्होंने उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। मुद्गलपुराण में भी आता है कि परम पराक्रमी लोभासुर से त्रस्त होकर देवताओं ने परम प्रभु गजानन से उसके विनाश की प्रार्थना की।

दयाधाम गजमुख उस महान असुर के विनाश के लिए परम पावनी चतुर्थी को मध्याह्न काल में अवतरित हुए। इस कारण उक्त तिथि उन्हें अत्यंत प्रीति प्रदायिनी हुई। परम कारुणिक गणेश जी को अंतरहृदय की विशुद्ध प्रीति अभीष्ट है। श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक त्रयताप निवारक दयानिधान मोदकप्रिय सर्वेश्वर गजमुख दूर्वा के दो दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं तथा मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं जन्म, जरा मृत्यु का पाश नष्ट कर अपना दुर्लभमत परमानंदपूरित दिव्य धाम भी प्रदान कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो गणेश भक्त वर्ष भर निरंतर पूजन करते रहते हैं उनके घर में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती।

-पंडित प्रसाद दीक्षित

कैसे करें ग्रहों को प्रसन्न

सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। सुखों का भोग तथा दुख निदान मानव जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। फलित ज्योतिष सुख-दुख का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। जीवन के सम्पूर्ण सुख-दुख, हानि, जय-पराजय आदि विषय 'ग्रहों' पर आधारित हैं। ये ग्रह 'सत्ताइस नक्षत्र' एवं 'बारह राशियों' पर भ्रमण करते हैं। अनिष्ट ग्रह जब मानव को पीड़ा देते हैं तब वह उनके शमन के उपाय खोजता है। भारतीय ज्योतिष ग्रंथ तथा धर्मशास्त्र इस मामले में मानव की सहायता करते हैं तथा इनमें अनिष्ट ग्रह पीड़ा निदान के अनेक उपाय बताए हैं। इन उपायों में रत्नधारण, जप व ग्रह शांति प्रमुख हैं। इस लेख में हम ग्रहों को प्रसन्न कर कष्ट दूर करने हेतु उपाय बता रहे हैं।

1. रवि : पौराणिक आख्यानों में रवि को कश्यप मुनि तथा अदिति का पुत्र कहा जाता है। इसी कारण रवि का प्रसिद्ध नाम आदित्य है। वेदांत दर्शन में रवि को जगत जीवात्मा कहा जाता है। रवि के बुरे प्रभाव से प्रभावहीनता तथा नेतृत्व गुणों का अभाव होने लगता है।

रवि को प्रसन्न रखने के लिए गेहूं, तांबा, सोना, लाल वस्त्र, गाय एवं माणिक्य दान करना चाहिए। बादाम धर्मस्थान में दान देना व तांबे को पानी में चढ़ाने से रवि की कृपा प्राप्त होती है। पितृ पूजा से रवि प्रसन्न होते हैं। कनेर, नागरमोथा, देवदारू, केसर, मनसिल, इलायची तथा महुआ के फूल पानी में उबाल कर स्नान करने से रवि की कृपा प्राप्त होती है।

2. चंद्रमा : फलित ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारकत्व प्राप्त है। शिव की आराधना चंद्रमा को प्रिय है तथा सरस्वती उपासना भी फल देती है। पंचगव्य मोती, चावल, घी से भरा कलश, कपूर, बैल, दही, शंख तथा मोती चंद्रमा के दान हैं। लाल किताब वर्षा जल, चावल तथा चांदी को सदा पास रखकर चंद्र कृपा प्राप्त करने की सलाह देती है।

3. मंगल : विवाह में मंगल दोष से सभी परिचित हैं। मंगल विवाह में विलम्ब भी उत्पन्न करता है। हमारी राय में अष्टम मंगल ज्यादा कष्टकारी है। इस दोष को दूर करने के लिए पंचमुखी दीप जलाकर पंचोपचार (गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य) से मंगल ग्रह की पूजा कर मंगल चंद्रिका स्तोत्र के 108 दिन तक पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन 7 या 21 पाठ किए जा सकते हैं। मां गौरी का पूजन तथा पार्वती मंगल का पाठ मंगल को प्रिय है। हनुमान जी की आराधना मंगल की कृपा दिलवाती है।

मंगल की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल चंदन, लाल पुष्प, बिल्वपत्र, जटामांसी, मौलश्री, हींग, मालकांगनी, सिंगरिक के चूर्ण से स्नान करना शुभ है। काले कुत्ते को घी-गुड़ रोटी खिलाना तथा योग्य व्यक्ति को मूंगा, गेहूं, मसूर, लाल बैल, गुड़, सोना, तांबा तथा लाल वस्त्र दान करना चाहिए। मीठा भोजन, मिठाई और बताशे के दान को लाल किताब श्रेष्ठ उपाय बताती है।

4. बुध : लाल किताब के अनुसार तांबे का टुकड़ा सुराख करके पानी में बहाना बुध के लिए उत्तम है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार पन्ना, चावल गौरोचन, शहद, सोना, जायफल, पीपरमूल तथा गाय के गोबर से मिश्रित जल से स्नान करने से बुध उत्तम फल देते हैं। नीला वस्त्र, हरा फूल, सोना, पन्ना, मूंग, घी, कांसे के बर्तन, बुध के प्रसिद्ध दान हैं। बुध की कृपा के लिए भगवान गणेश व विष्णु की आराधना तथा उन्हें बुधवार को 108 नामों के साथ दूर्वा चढ़ानी चाहिए।

5. बृहस्पति : पौराणिक आख्यानों में बृहस्पति को अत्यंत शुभ तथा प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। इन्हें देवगुरु की उपाधि प्राप्त है। सरसों, गूलर, दमयंती, मुलहठी, शहद, चमेली के चूर्ण से स्नान करना बृहस्पति के लिए उत्तम है। पुखराज, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली दालें, नमक, पीला पुष्प, खांडसारी, शक्कर, गुड़ दान करने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी की आराधना तथा अमावस्या व्रत शुभ है।

6. शुक्र : यह काम का प्रतीक तथा भारतीय फलित ज्योतिष में दैत्य गुरु की उपाधि पाता है।

मैनसिल, जायफल, केसर, इलायची, मूल के बीज, हरड़ तथा बहेड़ा का चूर्ण पानी में मिलाकर स्नान करने से शुक्र की कृपा प्राप्त होती है। हीरा, चांदी, चावल, दही, मिश्री, सफेद पुष्प व कपड़े, चंदन तथा सफेद घोड़ा शुक्र के प्रमुख दान हैं। लाल किताब जप, गाय, कन्या तथा तेल दान शुक्र के लिए शुभ मानती है। संतोषी माता का व्रत, गौ पूजा तथा भगवती दुर्गा की आराधना करना शुक्र को प्रिय है।

7. शनि : शिव एवं भैरव की उपासना शनि की कृपा के लिए अत्यंत आवश्यक है। शनि की पीड़ा शांति के लिए लाल किताब तेल में अपनी छाया देखकर उसे पात्र सहित दान देने की सलाह देती है। नीलम, काले तिल, वस्त्र, काले पशु, कम्बल, लोहा, उड़द, तेल तथा जूते शनि के दान हैं। सौंफ, लोबान, खस, काले तिल के चूर्ण से स्नान उत्तम उपाय है। साढ़ेसाती व ढैया की उग्रता, शनि का मारक होना तथा अति कष्ट देने की स्थिति में महामृत्युंजय जप राहत देता है।

8. एवं 9. राहू व केतु : इन छायाग्रहों के दान, स्नान, देवता तथा उपासना शनि व्रत है। दान व स्नान में गोमेद, लहसुनिया, हाथी दांत तथा कस्तूरी को भी सम्मिलित करना चाहिए। लाल किताब कच्चे कोयले को पानी में बहाना, मसूर दान, जौ सिरहाने रखना, कुत्तों को रोटी खिलाना तथा तेल दान राहू-केतु के उपाय बताती है। आचार्य सुश्रुत ग्रह पीड़ा तथा रोग से मुक्ति के लिए प्रायश्चित करने को महत्व देते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट में महामृत्युंजय मंत्र का जप मनुष्य के प्राणों की रक्षा करता है। नवग्रह उपासना में ग्रहों के दान, ग्रहों के देवताओं की आराधना तथा औषधि स्नान से अनिष्ट ग्रहों से शांति मिलती है।

—आचार्य पं. रामचंद्र शर्मा वैदिक

मोरपंख घर में लगाना होता है शुभ

जानिए 7 चमत्कारिक उपाय

1. घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख को लगाना हमेशा शुभ होता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा और जीव-जंतु घर में प्रवेश नहीं कर पाते। इसके लिए 3 मोरपंख लगाकर 'ॐ द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापयै स्वाहा' मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं।
2. आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोरपंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लाकर तिजोरी में रख दें।
3. बुरी नजर से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोरपंख चांदी के ताबीज में पहनाएं।
4. यदि आपका बच्चा बहुत रोता है, चिढ़ता है या जिद्दी है तो छत के पंखों पर पंख लगाने से जिद कम हो जाती है।
5. अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं तो मोरपंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर, मंगलवार एवं शनिवार उनका नाम लेकर लगाएं और सुबह बिना मुंह धोए इसे बहते हुए पानी में बहा दें।
6. आग्नेय कोण में मोरपंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोरपंख लगाएं।
7. ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोरपंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छींटें दें और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई दे।

नया वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी

5 साल के लिए इंश्योरेंस लेना अनिवार्य नहीं

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बीमा नियामक IRDA ने नया वाहन खरीदने की योजना रहे लोगों के लिए राहत की खबर दी है। आईआरडीए ने कारों और मोटरसाइकिलों के लिए 3 साल और 5 साल के लॉन्ग टर्म कवरेज को वापस ले लिया है। यह नियम ऐसे वक्त में लागू किया गया है, जब कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं या वेतन में कटौती जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

पहले किया गया था अनिवार्य

वाहनों के लिए लॉन्ग टर्म कवरेज को 2018 के बाद से खरीदे गए सभी वाहन के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। IRDA ने कहा कि पॉलिसी को बेचना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि इसकी कीमत काफी अधिक होती थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने बीमाकर्ताओं के लिए अगस्त 2018 से कारों के लिए तीन साल की मोटर पॉलिसी और सितंबर 2018 से दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल की मोटर पॉलिसी अनिवार्य कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना कोई वाहन सड़क पर नहीं चलेंगी, इस फैसले के बाद यह और अधिक अनिवार्य हो गया था।

लॉकडाउन में बदला फैसला

कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बीमा कंपनियों को पूरी तरह से खत्म होने की आशंका के चलते यह दिशा-निर्देश लाया गया। साल की पहली तिमाही में देश में बंद के दौरान नए वाहनों की बिक्री न के बराबर हुई। लोगों की खत्म होती नौकरी और वेतन कटौती के बाद ये नियम थोड़े राहत देने वाले हो सकते हैं। नया वाहन खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए यह काफी राहत की खबर है, क्योंकि कई सालों के लिए बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुगतान कई ग्राहकों के लिए अतिरिक्त बोझ जैसा था। कई ऑटो डीलरों ने शहरों में अपने आउटलेट खोलना शुरू कर दिया है।

महज 1.37 रुपये रोज देकर कराइए ट्रेवल इंश्योरेंस

साल भर रेल, रोड, एयर में बेखौफ घूमिये

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आप नौकरी या कारोबार के सिलसिले में अक्सर घूमते रहते हैं और हर ट्रिप में अलग-अलग ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance policy) खरीदते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड इंडिया ने PhonePe के साथ मिल कर एक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस कवर (multi-trip insurance cover) निकाला है जिसमें एक साल के लिए 5 लाख रुपये का बीमा महज 499 रुपये में मिलेगा। दोनों कंपनियों की तरफ से जारी एक साझा बयान के मुताबिक इसके लिए एक रणनीतिक समझौता किया गया है, ताकि देश में पहली बार एक मल्टी ट्रिप ट्रैवल इंश्योरेंस पालिसी निकाली जा सके। यह पालिसी सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए है।

असीमित यात्रा में कवरेज

अभी तक हर ट्रिप के लिए अलग ट्रैवल इंश्योरेंस होता था। लेकिन इसने पहली बार एक ऐसा इंश्योरेंस कवरेज निकाला है जिसमें साल भर होने वाले असीमित सफर, चाहे वह रेलगाड़ी से हो, सड़क मार्ग से हो, जल मार्ग से हो या फिर वायु मार्ग से, सभी ट्रिप कवर होंगें। यह न सिर्फ कारोबार के सिलसिले में या दफ्तर के काम से यात्रा करने वालों के लिए बल्कि सैलानियों के लिए भी मुफीद होगा।

ट्रैवल के दौरान होने वाली दिक्कतें भी हैं इसमें शामिल

COVID-19 महामारी के दौरान बाहर निकलना थोड़ा खतरनाक हो गया है। ऐसे में यह कवरेज घरेलू यात्रियों के लिए अद्वितीय उत्पाद साबित हो सकता है क्योंकि इसमें ट्रिप कैंसिलेशन, ट्रैवल के दौरान घर में चोरी, कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होना, बैगेज मिसिंग तथा इस तरह के कई घटनाओं (trip cancellations, home burglary while travelling, missed connecting flights, lost baggage and more) को कवर किया गया है। यात्रा के दौरान दुर्घटना की वजह से बीमा कराने वाले को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है या उसकी मौत हो जाती है तो इसमें 5 लाख रुपये दिये जाएंगे।

अगर वाहन बाजार में मांग कमजोर बनी रही, कलपुर्जा कंपनियों बड़ी संख्या में नौकरी जाएगी : एक्मा

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाहन कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों के संगठन एक्मा ने चेतावनी दी है कि यदि वाहन क्षेत्र में मांग कमजोर बनी रहती है तो कलपुर्जा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां जाएंगी। वाहन कलपुर्जा क्षेत्र करीब 50 लाख लोगों को रोजगार देता है। पिछले साल वाहन कलपुर्जा कंपनियों के कारोबार में 18 प्रतिशत गिरावट देखी गयी। इस साल इसमें फिर से 20 से 40 प्रतिशत गिरावट की आशंका है।

ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एक्मा) ने कहा कमजोर मांग और पहले से मौजूद अतिरिक्त क्षमता के चलते वाहन कलपुर्जा कंपनियों को अपने कार्यबल में कटौती करनी होगी। ताकि कारोबार को व्यावहारिक बनाया रखा जा सके। एक्ता के अध्यक्ष दीपक जैन ने पीटीआई-भाषा से कहा, " जब तक मांग सही नहीं होती तब तक वित्तीय दबाव, नौकरी जाने और नकदी प्रबंधन से जुड़ी चिंताएं विद्यमान रहेंगी। यह हालात तभी दूर होंगे जब हम पहले जैसी स्थिति में लौट आएंगे।" उन्होंने कहा कि भले कंपनियां पूरी तरह से काम चालू कर दें लेकिन तब भी कमजोर मांग की वजह से उन्हें उतने कार्यबल की जरूरत नहीं होगी। जैन ने कहा, "ऐसी स्थिति में हम भले चाहें या ना चाहें, लोगों की नौकरियां जाएंगी। पहले यह गाज ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों पर गिरेगी, लेकिन बाद में यह अन्य पर भी इसका असर पड़ सकता है।" उन्होंने कहा कि वाहन विनिर्माताओं का संगठन सियाम पहले ही कोविड-19 की वहज से कारोबार में सालाना 35-40 प्रतिशत गिरावट आने का अंदेशा जता चुका है।

मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये बीमा कवर के बारे में अपना रुख स्पष्ट करें बीमा कंपनियां: इरडा

नयी दिल्ली। एजेंसी

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सभी बीमा कंपनियो से दिव्यांगों, एचआईवी/एड्स और मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये बीमा कवर के संदर्भ में अपना विचार और रुख सार्वजनिक करने को कहा है। बीमा कंपनियों से इस बारे में सूचना अपनी अपनी वेबसाइट पर देने को कहा गया है। इरडा ने एक परिपत्र में कहा कि सभी बीमा कंपनियां (जीवन, साधारण और स्वास्थ्य) को एक अक्टूबर तक निर्देशों का पालन करना है। बीमा नियामक के अनुसार उसका मानना है कि हर बीमा कंपनियों के लक्षित आबादी को उस दर्शन के बारे में सूचना होनी चाहिए जो उसकी बीमा कंपनियां प्रावधानों का अनुपालन करते समय अपनाती है।

बीएस-छह उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर लगाना होगा हरा स्टीकर

नयी दिल्ली। भारत चरण-छह (बीएस-छह) उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को एक सेंटीमीटर का हरा स्टीकर लगाना होगा। सरकार ने ऐसे वाहनों पर हरे स्टीकर को अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश एक अक्टूबर, 2020 से लाग होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, "बीएस-छह उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले वाहनों की तीसरी पंजीकरण प्लेट के ऊपर एक सेमी. की हरी पट्टी लगानी होगी। मोटर वाहन (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश, 2018 में संशोधन के जरिये यह आदेश जारी किया गया है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि एक अप्रैल, 2019 से सभी मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाई जाएगी, जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। एचएसआरपी विनिर्माताओं द्वारा नए प्रत्येक नए विनिर्मित वाहनों की विंडशील्ड के भीतर लगाई जाएगी। एचएसआरपी के तहत एक क्रोमियन आधारित होलोग्राम नंबर प्लेट के ऊपर बाईं ओर आगे-पीछे दोनों ओर लगाया जाएगा। तीसरी नंबर प्लेट में वाहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के अनुसार कलर कोडिंग भी होगी। कलर कोडिंग से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान हो सकेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बीएस-छह उत्सर्जन मानक एक अप्रैल, 2020 से लागू हैं। इसके तहत आग्रह आए हैं कि ऐसे वाहनों की पहचान अलग से हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य देशों में भी ऐसा होता है।

जीएसटी में कटौती, कबाड़ नीति से वाणिज्यिक वाहन उद्योग को उबारने में मदद मिलेगी : अशोक लेलैंड

नयी दिल्ली। एजेंसी

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती तथा वाहन कबाड़ नीति लाने से वाणिज्यिक वाहन उद्योग को उबारने में मदद मिलेगी। अशोक लेलैंड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विपिन सोंधी ने यह बात कही। हिंदुजा समूह की कंपनी ने कहा कि उद्योग में काफी समय से सुस्ती है। कोरोना वायरस की मार से बाजार और प्रभावित हुआ है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में वाणिज्यिक वाहन बाजार धीरे-धीरे उबरेगा। सोंधी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि निश्चित रूप से वाणिज्यिक वाहनों पर जीएसटी की दरों में कटौती से इस क्षेत्र को उबारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, "आप वाणिज्यिक वाहन उद्योग की ओर देखें तो यह देश का प्रमुख उद्योग है। इस पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगता है। उद्योग पहले से और अब भी जीएसटी दरों में कटौती की मांग कर रहा है। निश्चित रूप से यह एक प्रमुख मांग है।" उन्होंने कहा कि इसके अलावा वाहन कबाड़ नीति से भी इस उद्योग को मदद मिलेगी। साथ ही ग्रामीण भारत में निवेश बढ़ाने से भी यह उद्योग आगे बढ़ेगा। यह पूछे जाने पर कि वाणिज्यिक वाहन बाजार में बिक्री की स्थिति चालू वित्त वर्ष में कैसी रहेगी, सोंधी ने कहा कि बुनियादी रूप से हम देखें तो वाणिज्यिक वाहन उद्योग के प्रत्येक खंड का अलग रुख रहेगा। उन्होंने कहा कि स्थिति कैसी रहती है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार की ओर से जो सुधार किए गए हैं उनका प्रभाव क्या रहता है। इसके अलावा सही समय पर नकदी की उपलब्धता भी एक और कारक है जो उद्योग का रुख तय करेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तिमाही पिछली तिमाही से बेहतर रहेगी। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। वाहन विनिर्माताओं का संगठन सियाम सरकार से वाहनों पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग कर रहा है। सियाम का कहना है कि इसके अलावा सरकार को एक प्रोत्साहन आधारित कबाड़ नीति भी लानी चाहिए। सरकार का कहना है कि वह वाहन कबाड़ नीति पर काम कर रही है। हालांकि, वाहनों पर जीएसटी दर घटाने के बारे में सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं दिया गया है।

ASHOK LEYLAND

EPFO मेंबरों को मिलता है 6 लाख रुपये के बीमा कवर

नई दिल्ली। अगर आप भी ईपीएफओ मेंबर है तो आपके लिए खुशखबरी है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को बिल्कुल मुफ्त में 6 लाख रुपए का बीमा देती है। तो आइये जानते हैं कैसे मिलता है यह बीमा, कौन है इसके दावेदार और आपको मिला है या नहीं इसका लाभ? कोरोना और लॉकडाउन के बीच ये खबर आपको खुश कर सकती है। विपरित परिस्थितियों में परिवार के काम आने वाले बीमा के हकदार आप भी हो सकते हैं। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों और कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं देता रहा है। ऐसे में इस बीमा का लाभ परिवार को बीमारी, स्वाभाविक या दुर्घटना से हुई मृत्यु पर ही मिलता है।

हालांकि, इस बीमा का फायदा

सबको नहीं हो सकता है. जिसने अपने मृत्यु से 12 महीने पहले एक से अधिक संस्थान में कार्य किया हो उसी के परिवार इससे संबंधित क्लेम कर सकते है। आपको बता दें कि ईपीएफओ संगठन, इस बीमा को इंश्योरेंस स्कीम 1976 इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (उंश्ब) के तहत लाभ देता है। यह राशि सदस्यों के वेज का 20 गुना होता है अर्थात 6 लाख रुपए।

कैसे हो बीमा का भुगतान

सबसे पहले ये जान लें कि इसमें आपको कोई रकम अलग से जमा करने की जरूरत नहीं होती है। आप जिस संस्थान में कार्य कर रहे है, वहीं से प्रति माह आपके बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी ईपीएफ में जाता है। इधर, नियोक्ता भी इसी तरह से 12 फीसद कुछ और योगदान के साथ कटवाता है। यही नहीं, इसमें 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड और बची रकम ईपीएफ में चली जाती है। अतः कर्मचारी को अलग से कोई प्रीमियम जमा करने की जरूरत नहीं होती है।

प्रतिमाह कटने वाली राशि कितनी होती है

बीमे की प्रीमियम का अमाउंट कर्मचारी के सैलरी से ही कट जाता है। यह बेसिक सैलरी और भत्ते का 0.50 प्रतिशत होता है।

दावा करने के लिए क्या करें

मृतक के परिवार ही इस बीमा के राशि के हकदार हो सकते हैं। इसके लिए मृतक कर्मचारी ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, अर्थात जिस कंपनी में वह कार्य किया हो वहां उसका ईपीएफओ सेवा होना चाहिए। परिवार से दावा करने वाला व्यक्ति कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। क्लेम के दौरान मृत्यु प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी, अभिभावक सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट आदि जानकारी या कागजात जमा करने पड़ते है। जिसे नियोक्ता अथवा किसी गजेटेड अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है।

मॉनसून की रफ्तार तेज

अगले 48 घंटों में इन राज्यों में दे सकता है दस्तक

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में मॉनसून अगले 48 घंटे में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दस्तक दे सकता है। इधर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण चक्रवाती हवाओं के चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव क्षेत्र से मॉनसून को और गति मिलेगी और ये तेजी से आगे बढ़ेगा।

भारत के दक्षिणी हिस्से में आगमन के साथ ही मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। यह चेन्नई, चित्तूर, तुमुकुरु, शिमोगा, करवार को पार कर चुका है। अगले 48 घंटे में मॉनसून महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दस्तक दे सकता है। इधर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण चक्रवाती हवाओं के चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव क्षेत्र से मॉनसून को और गति मिलेगी और ये तेजी से आगे बढ़ेगा।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे मॉनसून को मिलने वाली गति के कारण अगले 24 घंटों के दौरान अरब सागर के मध्य में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ इलाकों में, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में, ओडिशा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर कोंकण और केरल में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा प्री-मॉनसून की गतिविधियों के चलते छत्तीसगढ़ और दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 12 जून तक भारी वर्षा की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य अरब सागर के ऊपर और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में मछुआरों को दूर रहने और समुद्र में नहीं उतरने की हिदायत दी है।

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक ने बचत खाते में जमा पर ब्याज बढ़ाया

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

जनता से जमा पूंजी आकर्षित करने के लिये लघु कर्जदाता बैंक इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक ने कहा कि उसने बचत खाते में एक लाख से लेकर पांच करोड़ रुपये तक की जमा पर बयाज दर को मौजूदा 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि नई दरें बुधवार से लागू होंगी। बैंक के अध्यक्ष और कंट्री प्रमुख (शाखा बैंकिंग, देनदारी, उत्पाद एवं संपत्ति) मुरली वैद्यनाथन ने कहा, ''हम एक लाख से लेकर पांच करोड़ रुपये तक की बचत जमा पर ग्राहक को 7 प्रतिशत सालाना दर से ब्याज की पेशकश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इससे बैंक के मौजूदा ग्राहकों और नये बचत खाता धारकों को बेहतर ब्याज दर के साथ अधिक जमा का अवसर उपलब्ध होगा।'' बैंक के बचत खाते में जमा की दो श्रेणियां हैं। पहली एक लाख रुपये और उससे ऊपर और दूसरी एक लाख रुपये तक की जमा पर बैंक ने ब्याज दर को 3.5 प्रतिशत पर यथावत रखा है। बैंक के पास करीब छह लाख बचत खाते हैं।

लॉकडाउन में इतने बिके पारले-जी बिस्कुट कि 82 साल का रेकॉर्ड टूट गया

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच भले ही तमाम बिजनस नुकसान झेल रहे हों, लेकिन पारले-जी बिस्कुट की इतनी अधिक बिक्री हुई है कि पिछले 82 सालों का रेकॉर्ड टूट गया है। महज 5 रुपए में मिलने वाला पारले-जी बिस्कुट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए भी खूब मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीद के खाया, तो किसी को दूसरों ने मदद के तौर पर बिस्कुट बांटे। बहुत से लोगों ने तो अपने घरों में पारले-जी बिस्कुट का स्टॉक जमा कर के रख लिया।

82 सालों की रेकॉर्ड सेल

पारले-जी 1938 से ही लोगों के बीच एक फेवरेट ब्रांड रहा है। लॉकडाउन के बीच इसने अब तक के इतिहास में सबसे अधिक बिस्कुट बेचने का रेकॉर्ड बनाया है। हालांकि, पारले कंपनी ने सेल्स नंबर तो नहीं बताए, लेकिन ये जरूर कहा कि मार्च, अप्रैल और मई पिछले 8 दशकों में उसके सबसे अच्छे महीने रहे हैं।

कंपनी की ग्रोथ में 80-90 फीसदी हिस्सेदारी

पारले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी हेड मयंक शाह ने कहा कि कंपनी का कुल मार्केट शेयर करीब 5 फीसदी बढ़ा है और इसमें से 80-90 फीसदी ग्रोथ पारले-जी की सेल से हुई है।

इसलिए कंपनी को हुआ फायदा

कुछ ऑर्गेनाइज्ड बिस्कुट निर्माताओं जैसे पारले ने लॉकडाउन के कुछ ही समय बाद ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। इनमें से कुछ कंपनियों ने तो अपने कर्मचारियों के आने-जाने तक की व्यवस्था कर दी थी, ताकि वह आसानी से और सुरक्षित तरीके से काम पर आ सकें। जब फैक्ट्रियां शुरू हुईं, तो इन कंपनियों का फोकस उन प्रोडक्ट्स का उत्पादन करना था, जिनकी अधिक सेल होती है। हाल ही में एफएमसीजी प्लेयर्स पर एक स्टडी करने वाले क्रिसिल रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर अनुज सेठी कहते हैं कि ग्राहक हर वो चीज खरीद रहे थे, जो मिल रही थी। भले ही वह प्रीमियम हो या इकनॉमी। कुछ प्लेयर्स ने तो प्रीमियम वैल्यू पर ही फोकस किया। इन सभी प्लेयर्स ने पिछले 18-24 महीनों में अपना डिस्ट्रिब्यूशन बढ़ाने पर फोकस किया, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कोरोना वायरस महामारी के दौर में उनकी वो मेहनत रंग लाई।

ब्रिटानिया के बिस्कुट भी खूब बिके

सिर्फ पारले-जी ही नहीं, पिछले तीन महीनों में लॉकडाउन के दौरान बाकी कंपनियों के बिस्कुट भी खूब बिके। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रिटानिया का गुड डे, टाइगर, मिल्क बिकिस, बार्बर्न और मैरी बिस्कुट के अलावा पारले का क्रैकजैक, मोनैको, हाइड एंड सीक जैसे बिस्कुट भी खूब बिके।

लॉकडाउन में की लोगों का इकलौता खाना था पारले-जी

पारले प्रोडक्ट्स ने अपने सबसे अच्छे बिकने वाले, लेकिन कम कीमत वाले ब्रांड पारले-जी पर फोकस किया, क्योंकि ग्राहकों की ओर से इसकी खूब डिमांड आ रही थी। कंपनी ने अपने डिस्ट्रिब्यूशन चैनल को भी एक हफ्ते के अंदर रीसेट कर दिया, ताकि रिटेल आउटलेट पर बिस्कुट की कमी ना हो। मयंक शाह कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान पारले जी बहुत से लोगों को आसान खाना बन गया। कुछ के लिए तो यह उनका इकलौता खाना था। जो लोग रोटी नहीं खरीद सकते वह भी पारले-जी बिस्कुट खरीद सकते हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।